

अध्याय IV

संयुक्त उद्यमों में नीतिगत निवेश

कम्पनी ने इस्पात संयंत्रों की स्थापना और कोयला और लौह अयस्क खदानों के विकास के लिए भारत में निजी कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों के अलावा विभिन्न केन्द्र सरकार और राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) समझौते किये थे। 31 मार्च 2017 के अन्त तक जेवी में कम्पनी द्वारा किये गये इक्विटी योगदान के ब्यौरे निम्न तालिका में दर्शाये गए हैं:

तालिका 4.1- संयुक्त उद्यमों में एनएमडीसी लि. के इक्विटी योगदान के ब्यौरे

सहायक/संयुक्त उद्यम के नाम	संगठन/अधिग्रहण की तिथि	एनएमडीसी का शेयरधारण (%)	इक्विटी में निवेश (₹ करोड़ में)
जे एण्ड के मिनरल डिवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	19.05.1989	95.86	28.51
नीलाचल इस्पात निगम लि.	08.12.2004	12.87	100.60
कृष्णापट्टनम रेलवे कम्पनी लि.	13.10.2006	14.82	40.00
इंटरनेशनल कोल वेन्चर्स (प्रा.) लि.	14.01.2009	26.47	376.36
लेगेसी आयरन ओर लि. पर्थ, आस्ट्रेलिया	21.12.2011	78.56	168.53
कुल			714.00

जेवी में कम्पनी द्वारा किये गए निवेश में कमियां देखी गई जिसकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

4.1 जे एण्ड के मिनरल डिवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू में निवेश

कम्पनी के पास जम्मू और कश्मीर राज्य में (लगभग 4.853 वर्ग कि.मी. क्षेत्र तक विस्तारित) पंथल में कम सिलिका मैग्नेसाइट डिपोजिट का खनन पट्टा था। पंथल गाँव में (डिपोजिट से लगभग 9 किमी. दूरी पर) 30,000 टीपीए (टन प्रति वर्ष) क्षमता के डेड बर्न्ट

मैग्नेसाइट (डीबीएम³²) के विनिर्माण संयंत्र को स्थापित करने और खदान को विकसित करने के लिए, कम्पनी ने क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत के अनुपात से एनएमडीसी और जे एण्ड के मिनरलस लिमिटेड (जेएण्डकेएमएल - जम्मू और कश्मीर सरकार का उपक्रम) के बीच इक्विटी भागीदारी के साथ जेएण्डकेएमएल के साथ जे एण्ड के मिनरल डिवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेएण्डकेएमडीसी) के नाम पर एक संयुक्त उद्यम कम्पनी (जेवीसी) का गठन किया (19 मई 1989)। प्रस्तावित परियोजना पवित्र धार्मिक स्थल श्री माता वैष्णो देवी की परिधि में स्थित है। श्राईन बोर्ड ने पट्टा करार और एमएमडीआर³³ अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपने स्वामित्व वाली व खनन पट्टे क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि के संबंध में प्रवेश अधिकार जारी किया (18 जुलाई 1990)। कम्पनी प्रारंभ से कच्चा मैग्नेसाइट विक्रय करने के लिए अभिप्रेत थी परन्तु मांग में कमी के कारण इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। इसके अतिरिक्त मूल्य आधारित उत्पादों जैसे कैल्साइंड मैग्नेसाइट के उत्पादन करने के लिए कम्पनी के प्रयासों को उच्च माल भाड़ा प्रभार, स्थानीय हानि, उच्च कर और 2005-06 तक विदेशी बाजारों से अधिक आपूर्ति के अलावा ग्राहक आधार लघु स्तर उत्पादक होने के कारण आगे नहीं बढ़ाया गया। बाद में जब डैड बर्ण्ट मैग्नेसाइट का बाज़ार बढ़ा, एम.एन. दस्तुर एण्ड कं. प्रा. लि. कोलकाता को ₹4.54 करोड़ की कुल लागत पर परियोजना के लिए ईपीसीएम परामर्शदाता नियुक्त किया गया (अप्रैल 2010) और क्योंकि श्राईन बोर्ड के पास भूमि का स्वामित्व निहित था, श्राईन बोर्ड को कुल मौजूदा मूल्य (एनपीवी)/क्षतिपूर्ति वनरोपण प्रभारों आदि हेतु ₹2.36 करोड़ का भुगतान किया। खनन पट्टा जेवीसी के नाम पर हस्तांतरित किया गया था (अप्रैल 2011) और परियोजना के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (13 मार्च 2012) के तहत मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी (03 मई 2011) जेवीसी को प्राप्त हुई थी। ईपीसीएम परामर्शदाता ने ठेका देने का पत्र जारी करने की तिथि से 38 महीनों की अवधि (अर्थात् 12 जून 2013 तक) के अन्तर्गत सम्पूर्ण कार्य को पूरा करना था जिनको पांच पैकेजों में बांटा गया था जैसे- (1) टैकनोलॉजी पैकेज (2) विद्युतीय प्रणाली, (3) मिट्टी की जांच, (4) शेष सिविल और संरचनात्मक कार्य, (5) परियाजना के लिए परिचालन और अनुरक्षण (ओएण्डएम) हेतु एजेंसी की नियुक्ति। परियोजना की पूंजीगत

³² डीबीएम (मैग्नीशियम ऑक्साइड - एमजीओ), कार्बन डाइऑक्साइड तत्व को खत्म करने के लिए 1700 डिग्री सेल्सियस से 2300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करके मैग्नेसाइट (एमजीसीओ₃) से उत्पादित एक हार्ड/रॉक ठोस/उच्च तापमान प्रतिरोधी व उच्च भार उठाने की क्षमता (उच्च तापमान के तहत) वाली सामग्री है और स्टील बनाने/गैर लौह धातु निकालने/ग्लास बनाने की भट्टियों में व्यापक रूप से अपवर्तक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है।

³³ खदान और खनिज संपदा विकास और विनियमन अधिनियम, 1957

लागत ₹243.70 करोड़ (संशोधित) थी और ओएण्डएम पैकेज (सं.-5) को छोड़कर सभी पैकेजों के कार्य नवम्बर 2011 और मई 2015 के बीच दिये गए थे।

हमने देखा कि:

- (क) कम्पनी ने 18 महीनों की पूर्णता अवधि अर्थात् 20 नवम्बर 2016 तक के साथ ₹119.40 करोड़ (प्लस यूएस \$45,50,675) के मूल्य के लिए एफएल स्मिथ प्रा. लिमिटेड, चैन्नई के सहायता संघ को टैकनोलॉजी पैकेज असामान्य विलम्ब से दिया था (21 मई 2015)।
- (ख) इस दौरान, अक्टूबर 2016 में, एमओईएफएण्डसीसी ने यह कहते हुए परियोजना को दी गई पर्यावरण मंजूरी को वापस ले लिया कि प्राचीन पवित्र धार्मिक स्थान श्री माता वैष्णो देवी की निकट परिधि में खुली खदानों से खनन करना भुर-भुरे और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बन सकता है।
- (ग) कम्पनी द्वारा नियुक्त खनन और ईंधन अनुसंधान केन्द्रीय संस्थान, धनबाद की अध्ययन रिपोर्ट (फरवरी 2015), पर विचार किए बिना इसी को वापस लिया गया, जिसमें परिणाम निकाला गया था कि विस्फोट के कारण वहां कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा और कोई पत्थर गिरने की घटना नहीं होगी।
- (घ) एनएमडीसी के द्वारा जेवीसी को दिए गए अग्रिमो (₹17.97 करोड़) सहित जेवीसी में ₹42.37 करोड़ की राशि का निवेश पहले ही किया जा चुका था जिसे 2016-17 में खाता बही के बड़े खाते में डाला गया। अतः कंपनी द्वारा खर्च की गई सम्पूर्ण राशि निष्फल साबित हुई।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि:

- टैकनोलॉजी पैकेज को अंतिम रूप देने में विलम्ब³⁴ तकनीकी विनिर्देशों में संशोधनों के कारण तीन बार निविदाओं में परिवर्तन, वाणिज्यिक धाराओं, व बोलीदाताओं में से एक अर्थात् मैसर्स एचडीओएल के निष्पादन से संबंधित मुद्दों के कारण हुआ।
- इसके अतिरिक्त, भूमि के संभावित वैकल्पिक उपयोग जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र, अन्य खनिज आधारित उद्योग, औद्योगिक पार्क इत्यादि की स्थापना, का पता लगाने के लिए गठित टास्क फोर्स किसी भी वैकल्पिक परियोजना की पहचान नहीं कर सका जो कि पंथल में विकसित बुनियादी ढांचे और कार्य स्थल का उपयोग कर सकता था।

³⁴ तकनीकी पैकेज मई 2015 में प्रदान किया गया था, अर्थात् एम. एन. दस्तूर एंड कंपनी को ईपीसीएम ठेका प्रदान करने (अप्रैल 2010) के पाँच वर्ष बाद।

- कम्पनी अभी भी बिना विस्फोट की नवीनतम खनन तकनीकी का उपयोग किये बिना परियोजना के पुनः प्रवर्तन के लिए प्रबल रूप से मामले को आगे बढ़ा रहीं थी और इसलिए कम्पनी द्वारा विभिन्न पैकेज पर खर्च की गई ₹42.37 करोड़ की राशि को निष्फल नहीं माना जा सकता था।

टास्क फार्स को परियोजना सुविधाओं का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं मिला।

4.2 नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल), ओडिशा में निवेश

एनएमडीसी ने कोणार्क मेट कोक लिमिटेड (केएमसीएल), जो ओडिशा सरकार का एक पीएसयू है, में वर्ष 2002 के दौरान, मंकादनांचा लौह अयस्क डिपोजिट के आवंटन की प्रत्याशा में ₹49 करोड़ का निवेश किया, जो विवादित था। केएमसीएल को एक अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) द्वारा वर्ष 2004 में ले लिया गया था और कम्पनी ने अन्य शेयरधारकों को अभिदत्त नहीं किये गये हिस्से (₹7.07 करोड़) को शामिल करते हुए राइट्स इश्यू³⁵ को अभिदत्त करके एनआईएनएल में इक्विटी के ₹51.60 करोड़ (2010-11 के दौरान) का अतिरिक्त निवेश किया था, इस प्रकार कुल निवेश ₹100.60 करोड़ तक बढ़ गया।

हमने देखा कि:

- क) उचित प्रयास किए बिना, कम्पनी ने विवादित खनन पट्टे में निवेश किया जो वर्तमान तिथि तक अनिर्णीत बना हुआ था।
- ख) एनआईएनएल की वित्तीय स्थिति पर अपने आप यथोचित परिश्रम किये बिना आगामी ₹51.60 करोड़ का निवेश किया गया था, क्योंकि यह लगातार हानियां उठा रहीं थी और 2016-17 के लिए इसकी निवल संपत्ति (-) ₹175.14 करोड़ थी।

इस प्रकार, ₹100.60 करोड़ के निवेश से अभी तक कोई प्रतिफल नहीं मिला।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा पैरा पर कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि दो स्वतंत्र परामर्शदाताओं की समीक्षा के बाद एनआईएनएल के राइट्स इश्यू में निवेश किया गया था। उच्च स्तरीय समिति के द्वारा की गई आंतरिक यथोचित प्रक्रिया के अलावा उनकी रिपोर्ट पर एनएमडीसी द्वारा विधिवत रूप से विचार किया गया था।

³⁵ राइट्स इश्यू का मतलब पूर्व शेयरों को अपने अधिकार में रखने के अनुपात में मौजूदा शेयरधारकों के लिए एक कम्पनी द्वारा एक विशेष मूल्य पर शेयरों को प्रदान करना है।

हालांकि, विवादित खनन पट्टे से अवगत होने के बावजूद निवेश के कारणों पर कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

4.3 कृष्णापट्टनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड में निवेश

चैन्नई बंदरगाह से 2004-05 से लौह अयस्क के निर्यात को बंद करने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए एनएमडीसी सहित लौह अयस्क निर्यातकों /एफआईएमआई (भारतीय खनिज उद्योग संघ) ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में कृष्णापट्टनम बंदरगाह को पसंदीदा वैकल्पिक बंदरगाह के रूप में अभिज्ञात किया। क्रमशः 30:30:13 की इक्विटी अनुपात पर रेल विकास निगम लिमिटेड, कृष्णापट्टनम पोर्ट कम्पनी लिमिटेड और आन्ध्र प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित (अक्टूबर 2006) एसपीवी अर्थात् कृष्णापट्टनम रेलवे कम्पनी लिमिटेड (केआरसीएल) के माध्यम से साढ़े पांच वर्षों की पूर्णता अवधि से अनुमानित ₹587.49 करोड़ की लागत पर दो चरणों में आन्ध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले में कृष्णापट्टनम और ओबयूलवरीपल्ले के बीच नई रेलवे लाइन (113 किमी.) को विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया था। शेष 27 प्रतिशत की इक्विटी को लौह अयस्क निर्यातकों/सामरिक निवेशकों के लिए छोड़ा गया था जिसमें से 15 प्रतिशत का अधिग्रहण एनएमडीसी ने ₹40 करोड़ का योगदान देकर किया ताकि परिवहन लागत पर नियंत्रण और रेल रैकों के आवंटन में अधिमान्य निरूपण प्रशोधन प्राप्त किया जा सके। सभी प्रकार से चरण-। के कार्य (वेंकटाचलम और कृष्णापट्टनम के 20 किमी. सेक्शन) मार्च 2013 तक पूरे कर लिये गए थे और चरण-।। (ओबूलावरीपली से वेंकटाचलम के बीच 93 कि.मी. तक) के अंतर्गत के कार्य अभी भी प्रगति पर थे जिनको मार्च 2018 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित था।

हमने देखा कि एसपीवी रेलवे से चरण-। के परिचालन के माध्यम से प्राप्त राजस्व से संपूर्ण हिस्सा प्राप्त नहीं कर सका जिसके कारण चरण-।। के कार्यों के निष्पादन में विलम्ब हुआ था। इसके अतिरिक्त, एनएमडीसी को अपने निवेश पर कोई रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कर्नाटक राज्य से लौह अयस्क के निर्यात विक्रयों पर लगाये गए (मार्च 2012) प्रतिबंध को देखते हुए निकट भविष्य में बेल्लारी सेक्टर से आगे ओर निर्यातों की संभावना नहीं थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि एनएमडीसी ने केआरसीएल को राजस्व के बकाया शेयर को जारी करने के लिए रेलवे बोर्ड को लिखा था और यह भी सूचित किया कि वह आगे केआरसीएल में निवेश नहीं करेगा।

4.4 इंटरनेशनल कोल वेन्चर्स लिमिटेड में निवेश

विदेश से मेटलर्जिकल कोकिंग कोयले और थर्मल कोयले की आपूर्तियां पाने के उद्देश्य से स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनटीपीसी लिमिटेड व एनएमडीसी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (अगस्त 2007) किये गए और एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) अर्थात “इंटरनेशनल कोल वेन्चर्स लिमिटेड (आईसीवीएल)” को सभी पांच सत्वों द्वारा 2:2:1:1:1 के अनुपात से ₹ 3,500 करोड़ के आरंभिक योगदान के साथ मई 2009 में गठित किया गया। तदनुसार, एनएमडीसी को आईसीवीएल में इसके शेयर में अनुपातिक ₹ 500 करोड़ का निवेश करना आवश्यक था। एनटीपीसी (फरवरी 2012) और सीआईएल (फरवरी 2015) क्रमशः ₹ 1.40 करोड़ और ₹ 2.80 करोड़ के आरंभिक पूंजी योगदान के बाद आईसीवीएल से बाहर निकल गए। इसके परिणामस्वरूप शेष तीन हिस्सेदार अर्थात सेल, आरआईएनएल और एनएमडीसी के बीच आईसीवीएल में शेयर पूंजी के अनुपात को क्रमशः 48:26:26 से संशोधित किया गया (सितम्बर 2015)।

जुलाई 2014 में, आईसीवीएल ने मोजाम्बिक में स्थित कोयला परिसंपत्तियों और कोयला खदान अर्थात रियो टिंटो कोल मोजाम्बिक (आरटीसीएम) में अपनी स्वाधिकृत सहायक संस्था आईसीवीएल मॉरीशस, जिसे सितम्बर 2014 में निगमित किया गया था, द्वारा 65 प्रतिशत स्वामित्व हिस्सा अधिग्रहण करने का निर्णय लिया। आरटीसीएम में शेष 35 प्रतिशत हिस्सा टाटा स्टील के पास था। आरटीसीएम की परिसंपत्ति निवेश सूची में, बंगा में एक परिचालित खदान, जाम्बेजी और टेटे ईस्ट ग्रीनफिल्ड्स परिसंपत्तियों³⁶ को सम्मिलित किया गया था। मोजाम्बिक में उपरोक्त विदेशी कोयला खदान संपत्तियों से आईसीवीएल ने 2014 में हार्ड कोकिंग कोल (एचसीसी) के 2.3 मिलियन टन (एमटी) के उत्पादन का अनुमान लगाया। इस अनुमानित उत्पाद के प्रति, यह आकलित किया गया था कि 2017-18 तक एसपीवी के लाभ आरंभ होने तक संचित हानि के प्रति ₹481.10 करोड़ (यूएस \$80 मिलियन) की अतिरिक्त राशि को मुहैया करवाने की आवश्यकता के साथ ₹300.69 करोड़ (यूएस \$50 मीलियन³⁷) का खरीद प्रतिफल होगा, जिसके लिए टाटा स्टील ने भी अपने शेयर की हिस्सेदारी देनी थी। कुल अनुमानित पुंजीगत खर्च 2015 से 2021 तक के वर्षों के लिए रोलिंग स्टॉक के प्रति

³⁶ आईसीवीएल का ध्यान मुख्यतः बंगा खदान पर ही केन्द्रित था और जाम्बेजी और टेटे ईस्ट परिसंपत्तियों पर वह ध्यान नहीं दे रही थी।

³⁷ खरीद अनुमान और प्रस्तावित पुंजीगत खर्च और रोलिंग स्टॉक के परिवर्तन के लिए 1 जुलाई 2014 को आरबीआई द्वारा घोषित ₹60.1370 प्रति यूएस डॉलर की विनिमय दर को अपनाया गया।

₹811.85 करोड़ (यूएस \$135 मिलियन) की आवश्यकता से प्रथम तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014 से 2016 तक के लिए लगभग ₹4,588.45 करोड़ (यूएस \$763 मिलियन) था। कंपनी मार्च 2015 तक आईसीवीएल में ₹213.36 करोड़³⁸ का निवेश कर चुकी थी।

कंपनी ने आईसीवीएल में आगामी निवेशों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति नियुक्त (अगस्त 2015) की। अपनी रिपोर्ट (फरवरी 2016) में कंपनी ने देखा कि आईसीवीएल द्वारा 2014 के दौरान उत्पादन और राजस्व पर किये गए आरंभिक अनुमान अधिक आंके गए थे। यह भी देखा गया कि यह परियोजना अन्तरराष्ट्रीय मेट-कोल उद्योग लागत वक्र के चौथे चतुर्थांश³⁹ में आ रही थी। परिचालन जोखिम के सन्दर्भ में तकनीकी सलाहकार द्वारा संदर्भित जोखिमों के प्रति आईसीवीएल ने सावधानी नहीं बरती। इसके अलावा, तीन वर्षों (2014-16) के लिए ₹481.10 करोड़ (यूएस \$ 80 मिलियन) की अनुमानित हानि कम आकी गई थी क्योंकि अकेले 2013 के लिए आंतरिक समिति द्वारा आंकलित वास्तविक हानि ₹668.49 करोड़ (यूएस \$108 मिलियन⁴⁰ डॉलर) थी। इसके अलावा, आंतरिक समिति ने पोर्ट पर डिलीवरी की उच्च लागत और परियोजना का उद्योग लागत वक्र के चौथे चतुर्थक में होना, रन-ऑफ-माइन (आरओएम) में उच्च राख सामग्री के कारण कम पैदावार, रसद अवसंरचना की कमी के कारण खदान उत्पादन बढ़ाने में असमर्थता के मद्देनजर महत्वपूर्ण पूंजी निवेश और आस्ट्रेलियाई कोयले के समान ग्रेड के प्रति लागत के प्रतिस्पर्धी नुकसान, को देखा। इसके अलावा, टाटा स्टील से (अधिग्रहण के बाद) बेंगा खदान में 35 प्रतिशत की प्रतिबद्धता के बावजूद कोई योगदान नहीं मिला और इस तरह से समिति ने वर्ष 2019 तक ऋण और इक्विटी के लिए ₹2598.20 करोड़ के एनएमडीसी के जोखिम का अनुमान लगाया। आंतरिक समिति ने कहा कि कंपनी को पता था कि आईसीवीएल घाटे में चल रही परियोजना का अधिग्रहण कर रही है और आईसीवीएल में निवेश से बाजार की मौजूदा परिस्थितियों (फरवरी 2016) में अल्प और मध्यम अवधि दोनों में रिटर्न नहीं मिलेगा और लम्बी अवधि में, परियोजना को बनाए रखने और आईसीवीएल में आगे और निवेश करने की लागत काफी अधिक साबित होगी और यह बहुत अधिक जोखिम पैदा करेगा।

³⁸ ₹2.41 करोड़ (2011-12), ₹1.89 करोड़ (2012-13), ₹0.70 करोड़ (2013-14) व ₹208.36 करोड़ (2014-15)

³⁹ कोयला उद्योग लागत वक्र का चौथा चतुर्थांश कोयला उत्पादको के उस खंड को संदर्भ करता है जो कि अन्तरराष्ट्रीय कोकिंग कोल की कीमतों में गिरावट से सबसे पहले और सबसे बुरी तरह प्रभावित निर्माता है।

⁴⁰ केलेंडर वर्ष 2013 के लिए हानि थी, इसलिए 31 दिसम्बर 2013 को ₹61.8970 प्रति यूएस डॉलर की विनिमय दर को अपनाया गया था।

इसके अलावा, आईसीवीएल को अपने पत्र (जुलाई 2017) में टाटा स्टील ने अपनी आशंका व्यक्त की कि बेंगा कोल खदान अपने आस्ट्रेलियाई साथियों की तुलना में स्वाभाविक रूप से नुकसानदेह स्थिति में है और मध्यम से लंबे समय अवधि में अन्य प्रमुख कोयला उत्पादकों से पीछे रहने का अनुमान है। इसके अलावा, एक अंतिम चतुर्थक (क्यू-IV) कोयला खदान उत्पादक के रूप में, जो अंतरराष्ट्रीय कोकिंग कोल की कीमतों में गिरावट से सबसे पहले और सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं, यह लंबे समय में सबसे अच्छा मामला परिदृश्य में भी मुनाफा कमाने के लिए संघर्ष करेगा।

हमने देखा कि:

- क) इक्विटी शेयरिंग अनुपात के पुनर्गठन के कारण एनएमडीसी की पूंजी प्रतिबद्धता वर्तमान ₹500 करोड़ से बढ़कर ₹910 करोड़ हो गई।
- ख) आईसीवीएल में आगामी निवेशों की जांच के लिए आंतरिक समिति नियुक्त (अगस्त 2015) करने, जिस समय तक कम्पनी आईसीवीएल में ₹213.36 करोड़ का निवेश कर चुकी थी, के बावजूद आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने (फरवरी 2016) से पहले कम्पनी ने आईसीवीएल में ₹107.97 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया। इसके अलावा, आईसीवीएल में ओर अधिक निवेश करने से बचने और पिछले 3-5 वर्षों के दौरान पहले से किए गए निवेशों की वसूली करने से सम्बंधित आंतरिक समिति की सिफारिशों (फरवरी 2016) के बावजूद, कंपनी ₹15.03 करोड़ के और निवेश के साथ आगे बढ़ी (जून 2016) और आईसीवीएल में ₹376.36 करोड़⁴¹ का कुल निवेश किया। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने यूएस \$30 मिलियन का लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जिसे आईसीवीएल द्वारा एक्सिस बैंक से कार्यशील पूंजी का ऋण प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।
- ग) आंतरिक समिति द्वारा उठाये गए मुद्दों की पुष्टि टाटा स्टील द्वारा नियुक्त (मार्च 2015) सलाहकार (आरपीएम-रुग्गे पिंकाँक्क मिनाको) ने भी की, जिसने कहा (जुलाई 2017) कि 2016-17 तक संचित घाटा ₹8,300 करोड़ (यूएस \$1.28 बिलियन) रहा और मूल्यांकन किया कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोकिंग कोल के दीर्घकालिक मूल्य पूर्वानुमान के मद्देनजर बेंगा कोयला खदान का ब्रेक-ईवन पॉइंट अभी भी दूर था।

⁴¹ ₹40 करोड़ के इक्विटी अग्रिम सहित

इस प्रकार, आईसीवीएल की अवास्तिक व्यावसायिक योजना के आधार पर कंपनी द्वारा किए गए ₹376.36 करोड़ के निवेश से अबतक कोई रिटर्न नहीं मिला है और मध्यम या दीर्घकालिक अवधि में उचित लाभ कमाने की अनिश्चितता बनी हुई थी।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि:

- मई 2016 में एक उच्च स्तरीय दल⁴² ने आईसीवीएल का निरीक्षण किया और पाया कि कम लागत पर प्रचालन परियोजना को अब भी व्यवहार्य बना सकते हैं। कम्पनी ने आईसीवीएल की इक्विटी में ₹15.03 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया।
- जबकि सितम्बर 2015 में एनएमडीसी बोर्ड द्वारा सेल, आरआईएनएल और एनएमडीसी के बीच इक्विटी शेयर पूंजी की पुनः संरचना का अनुमोदन किया गया, परियोजना के लिए कैपेक्स परिकल्पना के अनुसार अनुमोदित नहीं किया गया। जनवरी 2016 से अक्टूबर 2017 तक खनन प्रचालन बंद रहा। इसके अतिरिक्त कैपेक्स सीमा में वृद्धि का लेखापरीक्षा का विचार भी यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि कारोबार योजना बदल चुकी थी और आईसीवीएल घटी हुई लागत पर ही ठेकागत एजेंसियों के नये सेट द्वारा उक्त दर क्षमता पर ही चलती रही।

प्रबंधन का यह तर्क कि मोजाम्बिक में कम लागत का परिचालन व्यवहार्य होगा, आंतरिक समिति की टिप्पणी, कि यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय मेट-कोल उद्योग लागत वक्र के चौथे चतुर्थक (क्यू-IV) में थी, के विरोधाभासी था। इसके अतिरिक्त, टाटा स्टील (आरटीसीएम में संयुक्त उपक्रम साझेदार) के सलाहकार की रिपोर्ट उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करती है कि बेंगा खदान अपने ऑस्ट्रेलियाई साथियों की तुलना में हानि की स्थिति में थी। निश्चित रूप से इसी कारण से टाटा स्टील ने अधिग्रहण के बाद आरटीसीएम में और अधिक निवेश से अपने आप को अलग कर लिया था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि कोकिंग कोयला मूल्यों में भारी गिरावट के कारण और अधिग्रहण के दौरान प्रारंभिक अनुमानों की तुलना में उत्पादन की उच्च लागत के कारण संचित हानियां हुई थी। ऑस्ट्रेलियन \$180-\$190 पर कोकिंग कोयला के वर्तमान मूल्य के साथ यह परियोजना व्यवहार्य लगती है।

⁴² अध्यक्ष, सेल, संयुक्त सचिव, एमओएस, निदेशक (तकनीक), एनएमडीसी; निदेशक (वाणिज्यिक) आरआईएनएल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीवीएल शामिल हैं।

उत्तर विश्वासप्रद नहीं हैं क्योंकि परियोजना को वर्ष 2017-18 से लाभ अर्जित करना था और उसके लिए वर्ष 2016-17 तक ₹8,300 करोड़ (यूएस \$1.28 बिलियन) की संचित हानियों को पूरी तरह से समाप्त करना आवश्यक है, जिसमें काफी समय लग सकता है।

4.5 लिगेसी आयरन ओर लिमिटेड, आस्ट्रेलिया में निवेश

विदेश में खनिज संपत्ति के अधिग्रहण के लिए अक्टूबर 2009 के दौरान जारी किये गए ग्लोबल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंड्रस्ट (जीईओआई) के उत्तर में, आस्ट्रेलिया में विभिन्न खनिज/धातु डिपॉजिट्स के खनन अधिकार रखने वाली लिगेसी आयरन ओर लिमिटेड (एलआईओएल), आस्ट्रेलिया (आस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निकाय) ने पिलबरा क्षेत्र, आस्ट्रेलिया में स्थित राबर्टसन रेंज और हेमर्सले प्रोजेक्ट्स में अपने लौह अयस्क टेनमेंट⁴³ के दोहन के लिए कम्पनी से संपर्क किया (अगस्त 2010)। कम्पनी ने 432वीं बोर्ड मीटिंग (29 अप्रैल 2011) में एलआईओएल के राबर्टसन रेंज और हेमर्सले प्रोजेक्ट्स में 50 प्रतिशत शेयर अधिग्रहित करने का निर्णय लिया। कम्पनी ने मई 2011 में पाया कि एलआईओएल ने एक अन्य कम्पनी अर्थात् माऊट बेवन प्रोजेक्ट टेनमेंट के मालिक हॉथोर्न रिसॉर्सिज लिमिटेड के साथ 60 प्रतिशत लाभ के लिए फार्म-इन⁴⁴ जेवी समझौता किया था। इस प्रकार, मई 2011 में, कम्पनी ने एक मुख्य शेयर धारक जो कि आस्ट्रेलिया में वृद्धि प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेगी; के रूप में प्रबंधन नियंत्रण के लिए एलआईओएल में 50 प्रतिशत शेयर प्राप्त करने का निर्णय लिया। 12 प्रतिशत के रिटर्न की संभावित आंतरिक दर के साथ, 21 मई 2011 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये और कम्पनी ने एलआईओएल के साथ शेयर सब्सक्रिप्शन समझौता पूरा किया (20 अक्टूबर 2011) और ₹99.63 करोड़ (6.55 आस्ट्रेलियन सेंट प्रति शेयर की दर से आस्ट्रेलियन \$18.89 मिलियन) की लागत पर 28,83,62,699 शेयर जो कि आस्ट्रेलियन स्टॉक सक्सचेंज (एसएसएस) (21 दिसम्बर 2011) में सूचीबद्ध थे और एलआईओएल के 15,56,49,619 ओपशंस⁴⁵ (कुल

⁴³ टेनमेंट एक अन्वेषण लोइसेंस है जो खनिज स्थानों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए अनुमति प्रदान करता है।

⁴⁴ आस्ट्रेलियन अन्वेषण क्षेत्र में फार्म-इन-समझौते ठेकेदारी प्रबंधन में सामान्य बात है। विशिष्ट रूप से, किसी टेनमेंट में लाभ का मालिक (फारमोर) अन्य पार्टी (फार्मी) को उनके लाभ की प्रतिशतता को हस्तांतरित करने को सहमत हो जाता है यदि फार्मी विशिष्ट अन्वेषण प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है और अन्वेषण गतिविधियों के प्रति व्यय के निर्दिष्ट स्तर में सहयोग करता है।

⁴⁵ ओपशंस का आहवाहन वास्तविक बाजार मूल्य को ध्यान में रखे बिना निर्धारित मूल्य पर भावी तिथि पर निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले करके इन्हें इक्विटी में बदल दिया जाता है। ओपशंस के अधिग्रहण में नकद निर्गम नहीं होता जब तक कि यह वैध अवधि में प्रयोग नहीं किये जाते।

इक्विटी का 49.61 प्रतिशत) अधिग्रहित किये। कम्पनी का यह कदम आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) के नोटिस में भी लाया गया (22 नवम्बर 2012)। इसके अतिरिक्त, ₹3.40 करोड़ लगभग (आस्ट्रेलियन \$6,17,980) की लागत पर एलआईओएल पर अग्रोषण नीति तैयारी के लिए मई 2013 में एक परामर्शदाता के रूप में मैककिंसे एंड कम्पनी को नियुक्त किया जिसका विचार था कि माऊंट बेवन एक नकारात्मक निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) परियोजना थी और उन्होंने निवेश कम करने की सिफारिश की और हॉथोर्न रिर्सांसिज लिमिटेड में शेयर की खरीद रोकने की भी कम्पनी को सलाह दी। यद्यपि, संभावित दीर्घ अवधि संसाधन संवर्धन नीति के रूप में और अपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों को सुदृढ़ बनाने के मद्देनजर अपने कदम को सही ठहराते हुए एलआईओएल के राइट्स इशू को सबस्क्राइब करने के लिए कम्पनी आगे बढ़ गई (मार्च 2014)। कम्पनी ने एलआईओएल के राइट्स इशू को 1.40 आस्ट्रेलियन सेंट प्रति शेयर के प्रस्तावित मूल्य पर (प्रति शेयर के लिए 3 शेयरों पर) ₹68.90 करोड़ (आस्ट्रेलियन \$12.12⁴⁶ मिलियन (लगभग)) पर सबस्क्राइब किया, जिससे कुल निवेश ₹168.53 करोड़ (आस्ट्रेलियन \$31.01 मिलियन, अर्थात् अधिग्रहण के समय पर आस्ट्रेलियन \$18.89 मिलियन और अगस्त 2014 में अर्थात् राइट्स इशू के दौरान आस्ट्रेलियन \$12.12 मिलियन) की सीमा तक हो गया। कम्पनी ने अभी तक किसी ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया था। इस प्रकार, एलआईओएल में इक्विटी 49.61 प्रतिशत से बढ़कर 78.56 प्रतिशत तक हो गई। मार्च 2017 तक, एलआईओएल के पास एक लौह अयस्क टेनमेंट, 18 गोल्ड टेनमेंट और तीन मैटल टेनमेंट सहित 22 टेनमेंट थे।

हमने देखा कि:

- (क) अधिग्रहण प्रस्ताव लौह अयस्क और सोने के अनुमानित संसाधनों⁴⁷ के आधार पर अनुमोदित किया गया था और न कि साबित रिजर्व पर क्योंकि एलआईओएल परियोजनाएं अब भी अन्वेषण स्थिति में थी। यह दर्शाती है कि परियोजनाओं को वास्तविक दोहन से पहले उत्पादन पूर्व लम्बी अवधि से भी गुजरना था।
- (ख) जून 2011 तक (अधिग्रहण की तिथि तक) व्यय किये गये आस्ट्रे. \$9.995 मिलियन के अतिरिक्त, एलआईओएल ने मार्च 2017 तक 58 टेनमेंट के अन्वेषण पर आस्ट्रे. \$11.9 मिलियन का व्यय किया। इसके अतिरिक्त, 36 टेनमेंट आस्ट्रे. \$12.88

⁴⁶ $28,83,62,699$ मौजूदा शेयर * 3 * 1.4 सेंट प्रतिशेयर/100 = आस्ट्रेलियन \$12.12 मिलियन

⁴⁷ संयुक्त संसाधन रिजर्व समिति (जेओआरसी) के वर्गीकरण के आधार के अनुसार अनुमानित संसाधनों को संकेतित संसाधनों और फिर मापन योग्य या सिद्ध संसाधनों के रूप में वर्गीकरण के लिए के लिए अतिरिक्त अन्वेषण की आवश्यकता है।

मिलियन कुल व्यय के बाद वापस सौंप दिये गये जिसमें तीन कोयला टेनमेंट शामिल थे, जिससे मार्च 2017 तक कुल टेनमेंट 22 हो गये।

- (ग) एलआईओएल के टेनेमेंट्स के अधिग्रहण के समय, कंपनी के बोर्ड की उप-समिति ने अगस्त 2011 में देखा कि भारत में गाढ़े लौह अयस्क का अनुमानित उतराई-मूल्य लगभग ₹3,391.73 प्रति टन से ₹3,611.97 प्रति टन (यूएस \$77⁴⁸ प्रति टन से यूएस \$82 प्रति टन) होगा, जो कि अपने घरेलू खदानों से कंपनी की उत्पादन लागत⁴⁹ से बहुत अधिक सिद्ध होगा, जो भारत में अयस्क के आयात को बहुत महंगा बना देगा।
- (घ) मैक्किंज़े एण्ड कं., की मूल्य निर्धारण जांच के अनुसार माउंट बेवन आयरन ओर परियोजना एक नकारात्मक एनपीवी परियोजना थी और मध्यम अवधि के लिए एक सीमांत परिसंपत्ति थी और यह एनएमडीसी हेतु केवल लम्बी अवधि अर्थात् 2030 वर्ष के बाद से संभवतः सामरिक होगी जिसके लिए कंपनी को प्रत्येक वर्ष टेनेमेंट्स को स्वामित्व में बनाए रखने के लिए ₹89.67 लाख (1,77,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर⁵⁰) का न्यूनतम पर्यवेक्षण प्रतिबद्धता व्यय वहन करना होगा और आगे भी निवेश करना होगा चूंकि एलआईओएल का अपना राजस्व स्रोत नहीं है।
- (ङ) इसके अतिरिक्त, निम्न श्रेणी गुणवत्ता के लौह अयस्क (लौह तत्व 30.60 प्रतिशत) को ध्यान में रखते हुए, परियोजना की आर्थिक दृष्टि से लाभप्रदता अत्यधिक संदेहयुक्त थी चूंकि यह भारतीय इस्पात उद्योग की वर्तमान तकनीकी स्तर को देखते हुए व्यवहार्य नहीं हैं जैसा आईबीएम ने कहा (जुलाई 2009) कि 45 प्रतिशत फेरस ग्रेड (लौह) के लौह अयस्क को बेकार माना जाता है।
- (च) एलआईओएल के शेयर मूल्य में 03.11.2017 को प्रति शेयर 6.55 ऑस्ट्रेलियन सेंट के प्रारंभिक अधिग्रहित मूल्य से प्रति शेयर 0.30 ऑस्ट्रेलियन सेंट तक की गिरावट हुई थी। परिणामस्वरूप ₹151.40 करोड़ (27.55 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर) की कमी हुई क्योंकि ₹168.53 करोड़ (31.01 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर) का प्रारंभिक

⁴⁸ 01 अगस्त 2011 की आरबीआई संदर्भ दर एक यूएस डॉलर = ₹44.0485 को संपरिवर्तन के लिए लिया गया था।

⁴⁹ बैलाडीला सेक्टर में लौह अयस्क की उत्पादन लागत प्रति टन ₹1,000 से कम थी, जबकि आयातित अयस्क की उतराई लागत 2011 में प्रचलित प्रति यूएस डॉलर ₹45 की विनिमय दर को ध्यान में रखते हुए लगभग ₹3,465 प्रति टन थी।

⁵⁰ 18 दिसम्बर 2018 की आबीआई संदर्भ दर, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर = ₹50.6585, संपरिवर्तन करने हेतु मानी गयी थी।

निवेश उस समय तक घट कर ₹17.13 करोड़ (3.46 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर⁵¹) तक हो गया था।

इस प्रकार, एलआईओएल में कम्पनी द्वारा किया गया निवेश वित्त के तार्किक निर्धारण पर आधारित नहीं था जो कि सूचित जोखिम और रिटर्न प्रोफाईलिंग और भावी संभावनाओं से रहित था। कम्पनी के अविवेकपूर्ण निवेश का कदम वार्षिक आवर्तक अन्वेषण प्रतिबद्धता लागत और शेयर कमी के रूप में प्रदर्शित हुआ।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि:

- जब भी कई टेनमेंट्स में से एक खान में बदलता है, अन्वेषण परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कई गुणा बढ़ जाता है।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार 2025 तक और उसके बाद लौह अयस्क की कमी के अनुमान के मद्देनजर विस्तृत व्यवहार्य अध्ययनों के अन्तर्गत कम्पनी ने घरेलू इस्पात संयंत्रों को देने के लिए माउंट बेवन से लौह अयस्क आयात करने की योजना बनाई।
- विस्तृत व्यवहार्य अध्ययनों के अन्तर्गत ब्लास्ट फरनेस ग्रेड उत्पाद पर प्रीमियम दिलवाने वाले उत्पाद का उत्पादन करने के लिए माउंट बेवान के 30.60 प्रतिशत के लोह तत्व को 69 प्रतिशत से अधिक तक बेनीफिशिएट किया जा सकता है (डेविस ट्यूब रिकवरी टैस्ट के परिणाम)।
- एलआईओएल की जैसी अन्वेषण कम्पनियों के पास सतत राजस्व स्रोत नहीं था जब तक कि परियोजना उत्पादन न करने लगे जो कि कई वर्ष लेगी और एलआईओएल की मौजूदा बाजार कैप 0.60 ऑस्ट्रेलियन सेंट प्रति शेयर पर आस्ट्रे. \$8.81 मिलियन था। एलआईओएल में किसी सकारात्मक समाचार से बाजार कैप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता था।
- एलआईओएल ने तीन टंगस्टन टेनमेंट के आबंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये और अन्य टंगस्टन कम्पनियों के साथ बात कर रहे थे जिन्होंने व्यवहार्य अध्ययनों को पूरा कर लिया था, इसलिए, आस्ट्रेलिया में उपस्थिति देश और कम्पनी के लिए महत्वपूर्ण संसाधन लाभ को लक्ष्य करने में सहायता करेगी।

⁵¹ 3 नवम्बर 2017 की आरबीआई संदर्भ दर, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर = ₹49.5045, को परिवर्तन हेतु लिया गया।

उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है कि कम्पनी के प्रक्षेपण वैज्ञानिक और उपयुक्त स्वीकार्य आधारों के बजाय अपेक्षाओं तथा पूर्वानुमानों पर आधारित है। इसके अलावा, कम्पनी खदान से बंदरगाह तक अयस्क के परिवहन हेतु बन्दरगाह, रेलवे लाइन तथा सड़क मार्ग के निर्माण, विद्युत तथा विलवणन संयंत्र जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु किए जाने वाले व्यय, लौह अयस्क बेनिफिशिएशन लागत तथा अपने राजस्व प्रवाह के अभाव के कारण परियोजना की व्यवहार्यता व भारत में अयस्क के आयात पर अधिक प्रभाव डालने के अलावा टेनेमेंट्स बनाए रखने के लिए वार्षिक रूप से ₹89.67 लाख (आस्ट्रेलिया \$1,77,000) खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।